

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 25, शुक्रवार, १९४१-फरवरी 14, 2020 Magha 25, Friday, Saka 1941-February 14, 2020	

भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

### नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 13, 2020

**संख्या प.3(50)नविवि/03/2012 :-**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप-धारा (4) सपठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप-नियम (1) व नियम 10 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा दिनांक 17.06.1999 के पश्चात के प्रकरणों के संबंध में नगरीय क्षेत्रों (जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की लालकोठी योजना, जवाहरलाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फीट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र को छोड़कर) में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुज्ञा के उपरान्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के नियमन/आवंटन के लिए प्रीमियम की दरें निम्नानुसार निर्धारित करती है, अर्थात:-

**कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्रीमियम की दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड के वास्तविक पट्टा क्षेत्रफल पर)**

क्र.सं.	प्रयोजन	जयपुर			जोधपुर, अजमेर कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व भिवाड़ी के नगरीय क्षेत्र		कालम 3 एवं 4 में उल्लेखित नगरीय क्षेत्र को छोड़कर 50000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र	50000 तक की जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र
1	2	3			4		5	6
		नगर निगम सीमा के भीतर	नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान में वर्णित U-1 क्षेत्र	नगर निगम सीमा एवं मास्टर प्लान में वर्णित U-1 क्षेत्र को छोड़कर शेष जयपुर रीजन	नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र के भीतर	नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र	समस्त नगरीय क्षेत्र	समस्त नगरीय क्षेत्र
1	आवासीय (1) 200 व.मी. तक	260/-	140/-	110/-	180/-	140/-	110/-	80/-
	(2) 200 व.मी. से अधिक	350/-	210/-	160/-	260/-	210/-	160/-	110/-

	(3) ग्रुप हाउसिंग	260/-	140/-	110/-	180/-	140/-	110/-	80/-
2	वाणिज्यिक	1020/-	680/-	680/-	680/-	610/-	420/-	280/-
	(1) 200 व.मी. तक							
	(2) 200 व.मी. से अधिक	1360/-	680/-	680/-	1020/-	680/-	610/-	420/-

3	फार्म हाउस	520 रुपये प्रति व.मी. निर्मित क्षेत्र (गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र) पर
4	धार्मिक आध्यात्मिक व चेरिटेबल संस्था के अलावा अन्य संस्थान	प्रथम 40000 व.मी. तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
5	पर्यटन इकाई होटल/मोटल/रिसोर्ट/एम्प्लूजमेन्ट पार्क	प्रथम 20000 व.मी. तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
6	जन सुविधायें-अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थायें	प्रथम 10000 व.मी. तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
7	इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स- ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रान्सपोर्ट, कन्टेनर डिपो	प्रथम 20000 व.मी. तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत
8	औद्योगिक	प्रथम 5000 व.मी. तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर से एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत

परन्तु यह है कि:-

(1) उक्त वर्णित दरें दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेंगी, तत्पश्चात प्रति वर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (10 रुपये के अगले गणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दरें मानी जायेंगी।

(2) आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कार्नर भूखण्ड होने पर निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी।

#### स्पष्टीकरण:

(1) न्यूनतम आवासीय दर का आशय उस क्षेत्र में 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्ड के लिये निर्धारित प्रीमियम दर से है।

(2) राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।

(3) 'धार्मिक संस्थान' से तात्पर्य मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा व अन्य पूजा गृह से है। 'आध्यात्मिक संस्थान' से तात्पर्य विधिवत पंजीकृत किसी संस्था के सत्संग भवन से है।

(4) "अन्य संस्थानिक" से तात्पर्य राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) में परिभाषित "

संस्थागत प्रयोजन" से है, लेकिन इसमें उक्त स्पष्टीकरण संख्या 3 में वर्णित "धार्मिक संस्थान" और "आध्यात्मिक संस्थान" शामिल नहीं है।

(5) मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पर्यटन नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर सेन्टर की स्थापना हेतु 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित, सेवा नीति, सौर ऊर्जा नीति, अलाभकारी पंजीकृत चैरिटेबल संस्था (यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बालगृह) पर राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत छूट देय होगी।

(6) प्रीमियम की देय राशि में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराई गई राशि को समायोजित भी किया जायेगा।

(7) उक्त वर्णित दरों के आधार पर वसूली योग्य कुल राशि में से पूर्व में जमा करायी गई राशि समायोजित कर ली जावेगी। परन्तु अधिक जमा राशि (यदि कोई हो तो) वापिस नहीं लौटाई जावेगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टा विलेख या आवंटन पत्र जारी हो गया है, ऐसे प्रकरणों को प्रीमियम दरों के लिये पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
मनीष गोयल,  
संयुक्त शासन सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।